विचार बिन्दु

''जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।''- अरविन्द कटोच

केवल पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती निरस्त करने मात्र से क्या होगा, रोग की जड़ों का इलाज भी जरूरी है?

पुलिस सबइंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के जरिये 859 पीएसआई भर्ती होने थे।परीक्षा के तुरंत बाद से ही यह आरोप लगातार लगे कि परीक्षा के पेपर लीक हुए।पेपर ही लीक नही हुए,बहुत से आवेदको की जगह दूसरे व्यक्तिय परीक्षा में बैठे।आवेदन के साथ दस्तावेज भी नकली-फेक लगाए।ऐसे डमी परीक्षार्थी पास भी हुए और पीएसआई बनने के लिए चयनित भी हुए। पीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए 8 लाख के करीब युवकों में आवेदन किया और 3 लाख 80 हजार के करीब आवेदकों में परीक्षा दी थी। यह आंकड़ा बेरोजगारी की भयावह स्थिति की ओर इशारा करता है। ज्यादा धरना-प्रदर्शन होने पर, उस समय विपक्ष में और अब सत्ता पक्ष के वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा इस परीक्षा की सुचिता पर बार बार प्रश्न उठाने पर और कुछ सबूत सम्बंधित अधिकारियों के सामने रखने पर भी पूर्ववर्ती सरकार नें कोई जांच नही करवाई। चयनितों को पोस्टिंग ऑर्डर्स भी दे दिए।

वर्तमान सरकार नें चुनाव के समय इस प्रकार के सारे भर्ती फर्जीवाड़े को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। इस कारण सरकार को गहन जांच के लिए सारा प्रकरण पुलिस की शाखा एसओजी (स्पेशल ओप्रेसन ठ्रुप)को सौंपना पडा।अभी तक इस मामले में 53 प्रशिक्षु सब इन्सपेक्टर्स के साथ साथ इस फर्जीवाड़े में सहायक 103 दूसरे व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके।

अभी तक कि जांच से इतना साफ हो चुका है कि पीएसआई परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए, चयनित व्यक्तियों के लिए परीक्षा डमी लोगों ने दी। एसओजी में जो हेल्पलाइन जारी की थी उस पर हजारों की संख्या में शिकायतें,आपत्तियां आई है। इस भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर वर्तमान सरकार के एक बड़े राजनेता नें शुरू से विरोध किया।उनका ही कथन सही मानें तो उन्होंने बहुत से अहम सबूत सरकार व एसओजी को दिए है।

अब इस भर्ती से हुई नियुक्तियों का बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोप-) विरोध कर रही है जिसने इस मुद्दे पर विधान सभा के घेराव की भी चेतावनी दी है। इस मुद्दे का एक अन्य पक्ष भी है। चयनित पीएसआई लोगों से सहानुभूति रखने वाले उनके परिजन व मित्र लोग भी धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो चुने गए है उनमें बहुत से, बिना पेपर लीक का सहारा लिए, अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं। इन लोगों में ऐसे बहुत से लोग है जो पहले से विभिन्न सरकारी विभागों में सेवारत रहे है। ऐसे निर्दोष लोगों की नोकरियों पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अब यक्ष प्रश्न है कि चयनितों में से यह कैसे छंटनी हो कि किन लोगों ने पेपर लीक का फायदा उठाया और किन लोगों ने नहीं?

इसी बात की जांच लगातार एसओजी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एसओजी ने जांच के आधार पर यह माना है कि इस परीक्षा में पड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और इस परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा की सिफारिश की है।इस पर मंत्रिमंडल का निर्णय शेष है।प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।सरकार का जो भी निर्णय होगा उसका परीक्षण उच्च न्यायालय में होना ही है। लेकिन बात केवल पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की नहीं है,यह बीमारी बड़ी है।सत्ताधारी लोग की सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों व पोस्टिंग में सदा से ही चलती रही है। यह कुछ जनहित में होता है और कुछ स्व हित में होता है। 1998 से पहले भी यह बीमारी थी किंतु बड़े रूप में नहीं फैली थी।सत्ता के नजदीक के लोगों की कुछ सिफारिशें मानी जाती थी और कुछ प्रशासन के हित में नहीं मानी जाती थी।

1998 में डिजायर नाम की एक बीमारी ने व्यापक रूप धारण कर लिया। समय के साथ बीमारी कम होने के बजाय ओर अधिक बढ़ती गई।डिजायर संस्कृति का सार यह था कि स्थानीय विधायक या उस क्षेत्र के अन्य प्रभावशाली नेता जो सत्तासीन समूह के मर्जीदान थे उन्हें उनके क्षेत्र में कर्मचारियों के स्थानांतरण,पोस्टिंग करवाने में खुली छूट दे दी गाई। किस नेता के कहने से किस महकमे में ट्रांसफर आदि होते है ,यह गली मोहलों व बाजारों में चर्चा के विषय हो गए। लोकल लेवल के बाद बीमारी ने बड़े स्तर भी फैलना शुरू किया।संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों में सिफारिशें,अपना-पराया और काम का आदमी आदि पैमाने आधार बन गए।

> **अभी तक कि जांच से इतना साफ हो चुका है कि पीएसआई परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए, चयनित व्यक्तियों के लिए परीक्षा डमी लोगों ने दी। एसओजी में जो हेल्पलाइन जारी की थी उस पर हजारों की संख्या में शिकायतें, आपत्तियां आई है। इस भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर वर्तमान सरकार के एक बड़े राजनेता नें शुरू से विरोध किया। उनका ही कथन सही मानें तो उन्होंने बहुत से अहम सबूत सरकार व एसओजी को दिए है। अब इस भर्ती से हुई नियुक्तियों का बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विरोध कर रही है जिसने इस मुद्दे पर विधानसभा के घेराव की भी चेतावनी दी है। इस मुद्दे का एक अन्य पक्ष भी है। चयनित पीएसआई लोगों से सहानुभूति रखने वाले उनके परिजन व मित्र लोग भी धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो चुने गए है उनमें बहुत से, बिना पेपर लीक का सहारा लिए, अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं।**

नियुक्त होने वालों के कार्य कुशलता व क्षमता,उनकी व्यक्तिगत व संस्थागत निष्ठा आदि गौण हो गए।आरपीएससी, सेवा चयन बोर्ड आदि में नियुक्तियों इन्हीं उपरोक्त वर्णित पैमानों के आधार पर होने लगी।कौन सदस्य किस नेता का आदमी है अथवा कौन से ट्रैक से नियुक्त हुआ है,आम चर्चा के विषय हो गए।इस में नीचे से लेकर शीर्ष तक कड़ियां जुड़ गई। इन संस्थाओं के सदस्यों,वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत कर पेपर लीक होने लगे।पेपरलीक करने वालों और कुछेक कोचिंग संस्थाओं वालों के गिरोह सक्रिय हो गए। परिणाम यह हुआ कि 2018 से 2023के बीच अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की सुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगे।फेक दस्तावेजों, डमी कैंडिडेट्स के माध्यम से कई लोग सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पा गए और सही अभ्यर्थियों को उनकी सज्जनता का दंड मिल गया। पीएसआई भर्ती के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षक भर्ती,व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022,वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022,लेवल 1 अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक परीक्षा2018-19 तथा शिक्षा विभाग की अन्य भर्तियों में व्यापक गड़बड़ियों के आरोप लगे। अब आरोप तो सर्वविदित है। क्या राजनीतिक दलों के बयानवीर नेताओं में बयान भी खूब जारी किए किंतु क्या 2,4 भर्ती परीक्षाएं निरस्त हो जाएं या गहन जांच के बाद 100-50 को नौकरी से बर्खास्त हो जाए तो इस से रोग का अच्छा उपचार हो जाएगा? क्या रोग जड़ों से खत्म हो जाएगा या कम से कम लंबे अरसे तक रिपीट तो नहीं होगा? नहीं ,ऐसा नहीं होगा। जब तक नौकरियों के लिए परीक्षाएं,साक्षात्कार लेने वाली संस्थाओं में योग्य,निष्ठावान अध्यक्ष,सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी नहीं लगाएंगे तब तक एक बार जो बीमारी फैली है उसे जड़ों से खत्म करना मुश्किल होगा। सरकार के पास अधिकारियों का बड़ा बेड़ा होता है और उसमें योग्य निष्ठावान अधिकारी भी बहुत है। केवल ध्यान से,निष्पक्षता से चयन करना होगा,सिफारिशें को दर किनार करना होगा। जहां तक अध्यक्ष,सदस्यों की नियुक्तियों का प्रश्न है,इसके लिए सर्वप्रथम एक योग्य अधिकारियों,शिक्षाविदों आदि का सर्च पैनल गठित किया जाए।सर्च पैनल,प्रारंभिक तौर पर 40,50 व्यक्तियों की छंटनी करे।सरकार द्वारा इन के नाम सार्वजनिक किए जाए। जनता का फीडबैक लिया जाए।सर्वथा उचित पर गए व्यक्तियों में से 10,20 नाम शॉर्टलिस्ट कर मंत्रिमंडल के समुख चयन करने के लिए रखे जाएं। अंतिम निर्णय तो चुनी हुई सरकार को ही करना है किंतु स्वच्छ चयन की दिशा में यह प्रयास हो सकता है।सरकार के पास सलाहकारों की कमी नहीं,और बेहतर सुझाव लें और पूर्णतः आर्बिटररी चयन के स्थान पर कोई युक्तियुक्त ,काफी हद तक पारदर्शी,उचित मानदंडों पर आधारित प्रक्रिया अपनाई जाए जिस से जनता को लगे कि चयन योग्यता के आधार पर होता है और पूर्णतः भाई भतीजावाद के अनुसार नहीं। निर्णय तो सरकार को करना है। अनुभव यह बताता है कि कोई भी सरकार अपने स्वैच्छिक अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाती बल्कि अपनों को उपकृत करने में उनका उपयोग,दुरुपयोग करती हैं। आरोपों का क्या,पहले यह सत्ताधीश लगाते अब पहले वाले लगाते रहेंगे।जनता धरना प्रदर्शन करती रहेगा--सत्ता वालों के पास पुलिस है दुरुपयोग करने के लिए।

(महावीर सिंह, पूर्व आईएएस)

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर : सुशासन व सांस्कृतिक पुनर्निर्माण को समर्पित साधनामय जीवन

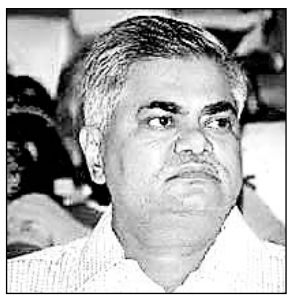

राजेश्वर सिंह

मराठा महासंघ के अंतर्गत इंदौर राज्य की तपस्विनी एवं तेजस्विनी शासिका अहिल्याबाई होल्कर अपने शौर्य, साहस, युद्ध कौशल, न्यायप्रियता, लोक कल्याणकारी प्रशासन, शिव भक्ति, त्याग और तपस्या से परिपूर्ण आध्यात्मिक जीवन तथा घ्वस्त धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार एवं नवनिर्माण की वजह से अपने जीवन काल में ही किंवदंती का रूप धारण कर चुकी थीं। उनकी उदारता, दयालुता ,परदुःख कातरता प्रशासनिक कुशलता व अतुलनीय धर्म निष्ठा के असंख्य किस्से आज भी मालवा व निमाड़ के क्षेत्र में प्रचलित हैं और जन सामान्य को व्यक्तिगत दुखों का साहसपूर्वक सामना करने तथा जीवन को परहित व लोकहित के लिए समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं।

अहिल्याबाई होल्कर का जन्म 31 मई को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर (अब अहिल्या नगर) जिले के ठाम चौंड़ी में हुआ था। उनके पिता गांव के पाटिल थे। वह बाल्यकाल से ही कुशाठा बुद्धि, साहसी व धर्म परायण थीं। इंदौर के सूबेदार मल्हार राव होल्कर के सैन्य अभियान पर जाते समय चौंड़ी गांव के शिव मंदिर में बालिका अहिल्याबाई से उनकी आकस्मिक मुलाकात हुई और उनके नैसर्गिक तेज और ओज से प्रभावित होकर मल्हार राव ने उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार 1733 ईस्वी में मात्र 8 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई मल्हार राव होल्कर के पुत्र खंडेराव की पत्नी बनकर मालवा में आ गईं। वहां उन्हें अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिला तथा मल्हार राव होल्कर की स्नेहिल छत्र छाया में न केवल उन्होंने शास्त्रों के पठन-पाठन में प्रवीणता अर्जित की वरन वे युद्ध कौशल एवं राजकीय प्रशासन की बारीकियों में भी निष्णात हो गईं। अहिल्याबाई का व्यक्तिगत जीवन असहनीय दुःख, व्यथा, वेदना और संताप से भरा हुआ था। 24 मार्च 1754 को एक युद्ध के दौरान उनके पति खंडेराव का दुःखद निधन हो गया।कुछ समय बाद 20 मई 1766 को उनके ससुर मल्हार राव होल्कर नहीं रहे। 5 अप्रैल 1767 को उनके एकमात्र पुत्र मालेराव भी चल बसे। इसके बाद होल्कर राज्य की बागडोर औपचारिक रूप से अहिल्याबाई के हाथ में आई जिसका कुशलता व तत्परतापूर्वक निर्वहन उन्होंने अपने सुयोग्य व शूरवीर सेनापति तुकाजी राव होल्कर की सहायता से किया। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में महेश्वर कस्बे में अपनी मृत्यु पर्यंत उन्होंने इस महनीय उत्तरदायित्व का वहन किया तथा व्यक्तिगत जीवन की शुचिता, राज कार्य की प्रबंधपटुता, निर्बल व असहाय के प्रति दया भाव, युद्ध क्षेत्र की वीरता व वैयक्तिक कोष से तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण के आध्यात्मिक उपक्रम से अभूतपूर्व यश, प्रतिष्ठा व लोकप्रियता का सार्वकालिक मानदंड स्थापित कर दिया।

उनका व्यक्तिगत व प्रशासनिक जीवन वैराग्य ,आध्यात्मिक साधना, निष्काम भाव से राज कार्य संपादन व सर्वतोमुखी लोकमंगल के प्रति पूर्ण समर्पण जैसे उच्चतम जीवन मूल्यों को समर्पित था। वे अप्रतिम शिव भक्त थीं और नित्य नैमित्तिक शिवपूजन के उपरांत ही अन्न-जल ठाहण करती थी।संपूर्ण राज्य उन्होंने अपने आराध्य देव को समर्पित कर रखा था। राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय वे अपना नाम न लिखकर श्री शंकर ही लिखती थीं। तब से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक इंदौर राज्य की समस्त राजाज्ञाएं श्री शंकर की आज्ञा से ही पालनार्थ निर्गत होती थीं। उनका रहन-सहन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे श्वेत वस्त्र धारण करती थीं तथा आभूषण व अलंकार इत्यादि का उपयोग नहीं करती थीं। उनकी दिनचर्या पूर्वाह्न में धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्रियाकलापों में व अपराह्न में राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन व निष्पादन में व्यतीत होती थी। अहिल्याबाई होल्कर ने जब राज्य का शासन सूत्र ठाहण किया तो राज्य में चोर ,डाकुओं का आतंक व्याप्त था जिससे जनसाधारण अत्यंत त्रस्त था। अहिल्याबाई ने यह घोषणा की कि जो वीर पुरुष इन उपद्रवियों को काबू में ले आएगा ,उससे मैं अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। यशवंत राव फडसे नामक एक साहसी युवक ने यह बीड़ा उठाया और थोड़े समय में ही उन्होंने दस्यु समस्या का उन्मूलन कर राज्य में शांति स्थापित कर दी। इसके उपरांत यशवंत राव व मुक्ताबाई का विवाह समारोहपूर्वक संपन्न हुआ। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित होते ही व्यापार, वाणिज्य व कला - कौशल में अभिवृद्धि हुई तथा महेश्वर ,जो अहिल्याबाई का मुख्यालय था, वस्त्र व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र बन गया। महेश्वर की यह स्थिति आज तक बदस्तूर बरकरार है। उन्होंने प्रशासन को सुव्यवस्थित कर राज्य को जिला एवं तहसीलों में विभक्त किया ,हर स्तर पर न्यायालय स्थापित किए व विवादों को स्थानीय स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए पंचायतों की स्थापना की। उनके प्रजानन कभी भी फरियाद लेकर सीधे उनके पास भी आ सकते थे। उन्होंने करारोपण की भी अत्यंत सरल पद्धित अपनाई जिसके अंतर्गत कर की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत कम होती थी ,फलतः कर की वसूली ज्यादा होती थी। उन्होंने विधवा महिलाओं को मृत पति का उत्तराधिकार प्रदान किया तथा शिक्षा एवं विशेष कर महिला शिक्षा की उन्नित के लिए विशेष प्रयास किये। उनकी न्यायप्रियता की ख्याति व प्रतिष्ठा का यह आलम था कि एक बार इंदौर व ग्वालियर राज्य के मध्य स्थित भूमि के विवाद के हल के लिए उन्हें ही न्यायाधीश मनोनीत किया गया जबकि वे स्वयं विवाद में एक पक्षकार थीं। उन्होंने उक्त विवाद का निर्णय भी अत्यंत तटस्थता व निष्पक्षतापूर्वक किया जिससे दोनों ही पक्ष सहमत व संतुष्ट हुए।

संपूर्ण भारतवर्ष में आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण, पुरातन देवालयों का जीर्णोद्धार, लगभग सभी पवित्र नदियों व सरोवरों पर घाट तथा धर्मशालाएं एवं स्थान-स्थान पर कुएँ एवं बावड़ियों का निर्माण इस धर्मपरायण शासिका की चिरस्थायी देन है, जिसके लिए धर्म प्रेमी जनता उनकी हमेशा ऋणी व कृतज्ञ रहेगी। उन्होंने सोमनाथ तथा काशी विश्वनाथ के खंडित देवालयों का पुनर्निर्माण किया व उनमें देव विठाह की पुनर्प्रतिष्ठा की। इस संबंध में यह उल्लेखनीय व स्मरणीय है कि यह सब कार्य उन्होंने इंदौर के राजकोष से वहन न कर शासक को जीवन निर्वाह हेतु प्राप्त होने वाली वैयक्तिक धनराशि में से किया था।

अहिल्याबाई होल्कर द्वारा शासित इंदौर कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, किंतु अपनी विलक्षण प्रतिभा, पावन चरित्र, अदम्य साहस, अनुपम त्याग, दुःसाध्य संयम, असीम उदारता, अद्भुत लोक निष्ठा व अतुलनीय धर्मपरायणता की वजह से उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपरिमित व अकल्पनीय ख्याति, प्रतिष्ठा, श्रद्धा व सम्मान अर्जित कर लिया। इतिहास में संभवतः वह एकमात्र रानी हैं जो अपने व्यक्तित्व व कृतित्व की वजह से लोक- स्मृति में लोकमाता के रूप में प्रतिष्ठित है। अतुलनीय धर्मपरायणता की वज़ह से उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपरिमित व अकल्पनीय ख्याति, प्रतिष्ठा,श्रद्धा व सम्मान अर्जित कर लिया। इतिहास में संभवतः वह एकमात्र रानी हैं जो अपने व्यक्तित्व व कृतित्व की वजह से लोक स्मृति में लोकमाता के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

-राजेश्वर सिंह
आईएएस (सेवानिवृत्त)

एम.एस.पी. घोषणा सकारात्मक पहल तो चाकचौबंद खरीद व्यवस्था भी जरुरी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा खरीफ की बुवाई से पहले ही करने को किसानों के हित में सकारात्मक पहल के रुप में देखा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा एक तो समय पूर्व समर्थन मूल्यों की घोषणा की जा रही है वहीं दूसरी और भविष्य की रणनीति के तहत आवश्यकतानुसार उत्पादन बढाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा श्री अन्न को जहां अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का सफल प्रयास किया गया है।

वहीं देश को दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। 2027 तक दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है तो तिलहन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आगामी खरीफ के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में रामतिल के भावों में सर्वाधिक 820 रु. की बढ़ोतरी करते हुए 9537 रु. प्रति क्विंटल एूमएसपी घोषित की गई है। इसी तरह से तिल की एमएसपी में 579 रु., सोयाबीन में 436 रु., सूरजमुखी में 441 रु. और मूंगफली की एमएसपी में 480 रु. की बढ़ोतरी की गई है। ठीक इसी तरह से उड़द में 400 रु. तो मूंग की एमएसपी में 86 रु. और अरहर की एमएसपी में 450 रु. की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से बाजरा, रागी, ज्वार, कपास, धान आदि अन्य खरीफ फसलों की एमएसपी दरों में बढ़ोतरी की गई है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां तक एमएसपी दरों की घोषणा की बात है सरकार की ईच्छा शक्ति पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार के 2013-14 से 2025-26 तक के कार्यकाल की एमएसपी दरों में बढ़ोतरी निश्चित रुप से सकारात्मक दिषा में बढ़ता कदम माना जा सकता है। 2013-14 की तुलना में 226 प्रतिशत की बढ़ोतरी रागी के समर्थन मूल्य में की गई है। बाजरा में 122 प्रतिशत तो ज्वार की एमएसपी में 147 प्रतिशत तक की बढोतरी हो चुकी है। दलहन और तिलहन की खरीफ फसलों में भी 82 प्रतिशत से रामतिल में 172 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सरकार का यह भी दावा है कि एमएसपी घोषणा करने से पहले सरकार ने फसलों की लागत के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है और लागत से कहीं अधिक एमएसपी दर जारी की गई है।

किसान आंदोलनों के दौरान सबसे अहम् मुद्दा एमएसपी को लेकर ही रहता आया है। सरकार एक और एमएसपी दरों में बढ़ोतरी और एमएसपी पर खरीद का दावा कर रही है और यह दावा एक हद तक सही भी है पर दूसरी और किसान नेताओं का यह कहना रहा है कि सरकार एमएसपी दरों की घोषणा के साथ ही एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। केन्द्र सरकार की और से एफसीआई और नेफैड एमएसपी खरीद के लिए नोडल संस्था है तो कपास की खरीद सीसीआई द्वारा की जाती है।

राज्यों में एफसीआई व नेफैड के लिए खरीद सुविधा में राज्यों की सहकारी विपणन संस्थाएं प्रमुखता से सहभागी रहती है। खरीद की व्यवस्था को भी पारदर्शी और ऑनलाईन कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे खातों में भुगतान तक की व्यवस्था ऑनलाईन की गई है। पर कहीं ना कही व्यवस्था में झोल अवश्य है। इसको यों समझा जा सकता है कि एक समय था तब सरकारी खरीद शुरु होने की घोषणा और लगभग 10 से 15 प्रतिशत उत्पादन की खरीद होते होते मण्डियों में भाव एमएसपी के आसपास आ जाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि ना तो किसानों की नाराजगी रहती थी और ना ही अन्य कोई समस्या आती थी।

पर आज खरीद व्यवस्था के पारदर्शी होने के बावजूद किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। इसका एक बड़ा कारण तो यह है कि बाजरा आदि की खरीद तो सरकार द्वारा किसी ना किसी बहानें टाली ही जाती है क्योंकि बाजरे की खरीद के बाद रखरखाव को लेकर संकट रहता है और सरकार का मानना है कि उसे नुकसान अधिक होता है क्योंकि खरीदा हुआ बाजरा जल्दी खराब हो जाता है। वहीं दूसरी और व्यवस्था को लाख पारदर्शी और जबावदेह बनाने के बावजूद बिचौलियें इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाते देखे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो खरीद केन्द्रों पर जितनी मात्रा में खरीद हो रही है वह उस क्षेत्र में उत्पादित पैदावार से भी अधिक हो जाती है।

इसके साथ ही किसानों की तात्कालीक आवश्यकताओं के चलते आड़तियों पर निर्भरता के कारण भी किसान का लाभ आड़तियां ले जाता है। हांलाकि यह व्यवस्था का ही दोष माना जा सकता है। होना तो यह चाहिए कि जिन फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है उन फसलों के तैयार होकर मण्डियों में आने से पहले ही सरकार को खरीद की आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। खरीद के लिए खरीद केन्द्र की स्थापना, तुलाई ढुलाई की व्यवस्था, बारदाना, ट्रांसपोर्टेशन, भण्डारण, भुगतान की आवश्यक व्यवस्था, बैंकों से भुगतान आदि की व्यवस्था, खरीद केन्द्रों पर पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था सहित आवश्यक सभी तैयारियां सुनिश्चित हो जानी चाहिए। इसके साथ ही आज सरकार के पास उत्पादन के सारे डेटा उपलब्ध होते हैं ऐसे में संभावित खरीद का आकलन भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए।

सरकार द्वारा पूर्व में ही यह घोषणा कि इतनी मात्रा में ही खरीद की जाएगी तो इससे राजनीति के अधिक अवसर उत्पन्न हो जाते हैं और अनावश्यक भ्रम के हालात बन जाते हैं। ऐसे हालात से बचा जाना जरुरी हो जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को खरीफ श्री अन्न खासतौर से बाजरा आदि की खरीद की भी स्पष्ट नीति बनानी होगी अन्यथा श्री अन्न खासतौर से बाजरा को हम अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म दिला रहे हैं वह जल्दी ही प्रभावित हो सकती है। सरकार को कोई ना कोई ऐसी स्पष्ट रणनीति बनानी होगी जिससे बाजरा उत्पादक किसान एमएसपी दर घोषित होने के बावजूद अपने आपकों ठगा महसूस ना कर सके। इसके लिए बाजार ताकतों को भी सक्रिय करना होगा ताकि बाजार में श्रीअन्न बाजरा आदि की मांग बढ़े और सरकारी खरीद ना होने की स्थिति में भी एमएसपी दर तो कम से कम उत्पादक किसान को बाजार में मिल सके। इसके लिए सरकार को इच्छाशक्ति के साथ आगे आना होगा। अब श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने का हमारा दायित्व भी हो जाता है।

ऐसे में इस और अधिक गंभीरता से ध्यान देना होगा क्योंकि अभी तो बुवाई से फसल पकने तक का तीन से चार माह का समय सरकार के पास होगा। इस क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी ठोस प्रयास करने होंगे ताकि इस समस्या का समाधान खोजा जा सके और अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिल सके। देर सबेर सरकार को खरीद को सीमा में बांधने के स्थान पर स्थाई हल खोजना होगा ताकि एमएसपी व्यवस्था और अधिक किसान हितेषी हो सकें।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

दो पार्थीव देह मेडिकल कॉलेज को सौंपी

बीकानेर, (निसं)। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के एनाटॉमी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. जुगल किशोर खत्री ने शुक्रवार को अपने पुत्र दीपक खत्री के निधन पर उनकी पार्थीव देह मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में सुपुर्द की। इस अवसर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. रेखा आचार्य पार्थीव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा दुःख की इस घड़ी में देहदान का निर्णय सर्वसमाज को प्रेरित करेगा जिससे सर्व समाज को कुशल चिकित्सक प्राप्त होंगे। इस दौरान शरीर रचना विभाग से डॉ. राकेश मणि, डॉ. कविता पाहुजा, डॉ. जसकरण सहित अन्य कार्मिकों एवं परिजनों आदि ने पार्थीव देह को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रंद्धाजलि दी।

समाजसेवी देवानी का निधन, पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को दान किया :- वहीं शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी, व्यापारी और देहदान आंदोलन के प्रेरक पवन देवानी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने जीवनभर देहदान और अंगदान को समर्पित रहे देवानी ने मृत्यु उपरांत भी अपना पार्थिव शरीर मेडिकल शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज को दान कर समाज के लिए अंतिम संदेश छोड़ गए। देहदान के इस पुण्य अवसर पर सिंधी समाज के कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. गुंजन सोनी ने भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वयं देहदान प्रक्रिया में भाग लिया और इसे एक सामाजिक संदेश करार दिया। यह क्षण न केवल पवन देवानी के जीवन मूल्यों का प्रतीक था, बल्कि समाज में देहदान और अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला भी बना।

देवानी का जन्म 26 मार्च 1944 को वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। भारत-पाक विभाजन के दौरान उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। महज 7 वर्ष की आयु में माता को खोने के बाद, उन्होंने चौथी कक्षा तक ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ज्ञान, सामाजिक जागरूकता और जीवन मूल्य उन्हें विरासत में मिले। उन्होंने न केवल व्यवसाय में पहचान बनाई, बल्कि मानवता, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। देवानी के पुत्र महेश देवानी ने बताया कि उनके पिताजी कहते थे, देहदान से मेडिकल छात्रों को मानव शरीर को समझने में मदद मिलती है, और यह एक सच्चा सामाजिक योगदान है। महेश देवानी ने बताया कि वर्षों से उनके पिता अपनी जेब में देहदान कार्ड लेकर चलते थे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहे। उनकी यह प्रतिबद्धता अंत तक बनी रही।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 31 मई, 2025

ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शनिवार, विक्रम सम्वत 2082, पुष्य नक्षत्र, रात्रि 9.07 तक, वृद्धि योग दिन 10.43 तक, बवकरण प्रातः 8.49 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-वृष, गुरु-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में संचार करेगा।

आज रवियोग रात्रि 9.07 से आरम्भ होगा। श्रुति पंचमी, महादेव विवाह है महापात्र योग दिन 11.58 से सायं 5.36 तक है। आज शुक्र अश्विनी मेष में दिन 11.33 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ 7.19 से 9.01 तक, चट 12.24 से 2.06 तक, लाभ-अमृत 2.06 से 5.29 तक

राहूकालः 9.00 से 10.30 तक, सूर्योदय 5.37 सूर्यास्त 7.11

मेष
घर-परिवार में सुख सुविधाऐं बडेगी। परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक मामले में संतुलन बनाये रखना ठीक रहेगा।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों-रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाऐ बडेगी।

सिंह
घर-परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अर्नगल कार्यों में समय खराब होगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है

कन्या
कन्या - आर्थिक वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल उंचा रहेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में आ रही अडचनें दूर होने लगेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

वृश्चिक